



જલસા એ દસ્તાવ બંદી

કા હૃદી આયોજન

ઇટકી। ઇટકી કે કુંડી ગાવ સિથ મદરસા જાળિયા અર્જિનિયા મેં આગામી 21 મેં રવિવાર કો એકદિવસીય જલસા એ દસ્તાર બંદી કાર્યક્રમ કા આયોજન કિયા ગયા હૈ। કાર્યક્રમ મેં મદરસા કે 19 વિદ્યાર્થીઓની કો 'હાફિઝ' કી ઉપાધિ પ્રદાન કી જાયેણી।

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



स्टारीय शिथा पर ध्यान

ज्ञा रस्वंड में अलग-अलग जिलों में स्थापित 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार की तर्ज पर इन स्कूलों में अत्यधिक आवासीय भूमि संचालन, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक लैब, डिजिटल स्मार्ट क्लास, लैंगवेचर लैब, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कम्प्यूटर ट्रेनिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक स्कूल सांस्कृतिक संस्कृत प्राप्त है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया कि इन सभी स्कूलों में कार्यों स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई होगी। मक्सद यह है कि सरकारी स्कूलों से पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं आज के प्रतियोगी बैरे में किसी से पीछे न रहें। इनके अलावा प्रधार्णों में 325 लीडर स्कूल और 4,091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। राज्य सरकार के मुताबिक इन विशिष्ट स्कूलों में 15 लाख से छात्र-छात्राओं को प्रधानाध्यापकों की ओर स्तरीय प्रशिक्षण दो चरणों में नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप द्वारा कराया जा सकता है। इन्हें अजमी प्रेसी फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। जनवरी माह में प्रधानाध्यापकों को आईआईएम की ओर से स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बच्चों को एग्रीकल्चर, आईटी, आईटीएम्स, अपरेल एण्ड मेडिप्रेस, मीटिंग्स, एंड एंटरटेनमेंट, आर्ट्समेट्रिक, ट्रॉफिज एण्ड हारिटेजलिटी समेत अन्य ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाएगा। संविधान ट्रेड से जुड़े राज्य स्तरीय प्रतियोगियों एवं संस्थानों के साथ इंडस्ट्रियल फॉर्ल विजिट की व्यवस्था की जा रही है ताकि भावी जीवन में उनके रुचि के अनुसार रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सके। हेमंत सरकार का यह सराहनीय कदम है।

बिन पानी सब सून

हि मालय के ग्लेशियर प्रिघलने की दर तेज होने से आकलन के

मुताबिक 2050 तक हिमालय के ग्लेशियर लगभग समाप्त हो जाएगे। इससे भूजल पर निर्भरता बढ़ेगी। भूजल का दोहन बढ़ा तो समूची दुनिया को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। इस समय देश में 61.6 प्रतिशत भूमि संरक्षित के लिए भूजल पर निर्भर है, केवल 24.5 प्रतिशत ही नहरों से सिंचित है। शेष पर अन्य पारंपरिक साधों से सिंचाई होती है। हाल वह है कि देश के लगभग एक तिहाई जिलों में स्थाई भूजल भंडार भी समाप्त हो गए हैं। इसलिए हमें उतना ही भूजल निकालना चाहिए जिनमा हर वर्ष पुनर्भरण से इकट्ठा होता है। इस आसन संकट को देख कर ही होने भूजल के मार्केट बनाने का चाहिए और उनका अनुश्रवण करना चाहिए भूजल के मार्केट के लिए भूजल के लिए भूजल के मार्केट तकनीकों से मेल खाने वाले कानूनों का भी अधार था दूसरे व्यवस्थित अनुश्रवण व्यवस्था नहीं थी। 2005 के कानून ने इस कमी को कुछ हद तक पूरा किया है। उससे पहले 1882 का एक कानून था जिसके अनुसार कोई भी अपनी जीमी के नीचे से भूजल दोहन कर सकता था। जाहिर है उस समय ऊर्जा चालित गहरे कुओं बनाने की तो कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं थी। लोग रेहट, कुओं आदि से भूजल दोहन करते थे, जिससे भूजल स्तर पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना ही नहीं रहती थी। आज जब एक ढेंड्र हजार फूट नीचे तक से भूजल का निकास संभव हो गया है तो सोचा जाएगा कि यह चाहिए। और उनका अनुश्रवण करना चाहिए भूजल के मार्केट में एक तो हायों पास वर्षानन तकनीकों से मेल खाने वाले कानूनों का अधार था दूसरे व्यवस्थित अनुश्रवण व्यवस्था नहीं थी। 2005 के कानून ने इस कमी को कुछ हद तक पूरा किया है। उससे पहले 1882 का एक कानून था जिसके अनुसार कोई भी अपनी जीमी के नीचे से भूजल दोहन कर सकता था। जाहिर है उस समय ऊर्जा चालित गहरे कुओं बनाने की तो कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं थी। लोग रेहट, कुओं आदि से भूजल दोहन करते थे, जिससे भूजल स्तर पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना ही नहीं रहती थी। आज जब एक ढेंड्र हजार फूट नीचे तक से भूजल का निकास करने के लिए अपने देशकालों से दूर होते देखना कुछ और नहीं बल्कि इसान के लिए अपने देशकालों से दूर होना है। इसलिए जब कोई विकास करने के लिए भूजल के लिए भूजल के मार्केट में एक तो हायों पास वर्षानन तकनीकों से मेल खाने वाले कानूनों का अधार था दूसरे व्यवस्थित अनुश्रवण व्यवस्था नहीं थी। 2005 के कानून ने इस कमी को कुछ हद तक पूरा किया है। उससे पहले 1882 का एक कानून था जिसके अनुसार कोई भी अपनी जीमी के नीचे से भूजल दोहन कर सकता था। जाहिर है उस समय ऊर्जा चालित गहरे कुओं बनाने की तो कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं थी। लोग रेहट, कुओं आदि से भूजल दोहन करते थे, जिससे भूजल स्तर पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना ही नहीं रहती थी। आज जब एक ढेंड्र हजार फूट नीचे तक से भूजल का निकास संभव हो गया है तो सोचा जाएगा कि यह चाहिए। और उनका अनुश्रवण करना चाहिए भूजल के मार्केट में एक तो हायों पास वर्षानन तकनीकों से मेल खाने वाले कानूनों का अधार था दूसरे व्यवस्थित अनुश्रवण व्यवस्था नहीं थी। 2005 के कानून ने इस कमी को कुछ हद तक पूरा किया है। उससे पहले 1882 का एक कानून था जिसके अनुसार कोई भी अपनी जीमी के नीचे से भूजल दोहन कर सकता था। जाहिर है उस समय ऊर्जा चालित गहरे कुओं बनाने की तो कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं थी। लोग रेहट, कुओं आदि से भूजल दोहन करते थे, जिससे भूजल स्तर पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना ही नहीं रहती थी। आज जब एक ढेंड्र हजार फूट नीचे तक से भूजल का निकास करने के लिए अपने देशकालों से दूर होते देखना कुछ और नहीं बल्कि इसान के लिए अपने देशकालों से दूर होना है। इसलिए जब कोई विकास करने के लिए भूजल के मार्केट में एक तो हायों पास वर्षानन तकनीकों से मेल खाने वाले कानूनों का अधार था दूसरे व्यवस्थित अनुश्रवण व्यवस्था नहीं थी। 2005 के कानून ने इस कमी को कुछ हद तक पूरा किया है। उससे पहले 1882 का एक कानून था जिसके अनुसार कोई भी अपनी जीमी के नीचे से भूजल दोहन कर सकता था। जाहिर है उस समय ऊर्जा चालित गहरे कुओं बनाने की तो कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं थी। लोग रेहट, कुओं आदि से भूजल दोहन करते थे, जिससे भूजल स्तर पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना ही नहीं रहती थी। आज जब एक ढेंड्र हजार फूट नीचे तक से भूजल का निकास करने के लिए अपने देशकालों से दूर होते देखना कुछ और नहीं बल्कि इसान के लिए अपने देशकालों से दूर होना है। इसलिए जब कोई विकास करने के लिए भूजल के मार्केट में एक तो हायों पास वर्षानन तकनीकों से मेल खाने वाले कानूनों का अधार था दूसरे व्यवस्थित अनुश्रवण व्यवस्था नहीं थी। 2005 के कानून ने इस कमी को कुछ हद तक पूरा किया है। उससे पहले 1882 का एक कानून था जिसके अनुसार कोई भी अपनी जीमी के नीचे से भूजल दोहन कर सकता था। जाहिर है उस समय ऊर्जा चालित गहरे कुओं बनाने की तो कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं थी। लोग रेहट, कुओं आदि से भूजल दोहन करते थे, जिससे भूजल स्तर पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना ही नहीं रहती थी। आज जब एक ढेंड्र हजार फूट नीचे तक से भूजल का निकास करने के लिए अपने देशकालों से दूर होते देखना कुछ और नहीं बल्कि इसान के लिए अपने देशकालों से दूर होना है। इसलिए जब कोई विकास करने के लिए भूजल के मार्केट में एक तो हायों पास वर्षानन तकनीकों से मेल खाने वाले कानूनों का अधार था दूसरे व्यवस्थित अनुश्रवण व्यवस्था नहीं थी। 2005 के कानून ने इस कमी को कुछ हद तक पूरा किया है। उससे पहले 1882 का एक कानून था जिसके अनुसार कोई भी अपनी जीमी के नीचे से भूजल दोहन कर सकता था। जाहिर है उस समय ऊर्जा चालित गहरे कुओं बनाने की तो कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं थी। लोग रेहट, कुओं आदि से भूजल दोहन करते थे, जिससे भूजल स्तर पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना ही नहीं रहती थी। आज जब एक ढेंड्र हजार फूट नीचे तक से भूजल का निकास करने के लिए अपने देशकालों से दूर होते देखना कुछ और नहीं बल्कि इसान के लिए अपने देशकालों से दूर होना है। इसलिए जब कोई विकास करने के लिए भूजल के मार्केट में एक तो हायों पास वर्षानन तकनीकों से मेल खाने वाले कानूनों का अधार था दूसरे व्यवस्थित अनुश्रवण व्यवस्था नहीं थी। 2005 के कानून ने इस कमी को कुछ हद तक पूरा किया है। उससे पहले 1882 का एक कानून था जिसके अनुसार कोई भी अपनी जीमी के नीचे से भूजल दोहन कर सकता था। जाहिर है उस समय ऊर्जा चालित गहरे कुओं बनाने की तो कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं थी। लोग रेहट, कुओं आदि से भूजल दोहन करते थे, जिससे भूजल स्तर पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना ही नहीं रहती थी। आज जब एक ढेंड्र हजार फूट नीचे तक से भूजल का निकास करने के लिए अपने देशकालों से दूर होते देखना कुछ और नहीं बल्कि इसान के लिए अपने देशकालों से दूर होना है। इसलिए जब कोई विकास करने के लिए भूजल के मार्केट में एक तो हायों पास वर्षानन तकनीकों से मेल खाने वाले कानूनों का अधार था दूसरे व्यवस्थित अनुश्रवण व्यवस्था नहीं थी। 2005 के कानून ने इस कमी को कुछ हद तक पूरा किया है। उससे पहले 1882 का एक कानून था जिसके अनुसार कोई भी अपनी जीमी के नीचे से भूजल दोहन कर सकता था। जाहिर है उस समय ऊर्जा चालित गहरे कुओं बनाने की तो कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं थी। लोग रेहट, कुओं आदि से भूजल दोहन करते थे, जिससे भूजल स्तर पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना ही नहीं रहती थी। आज जब एक ढेंड्र हजार फूट नीचे तक से भूजल का निकास करने के लिए अपने देशकालों से दूर होते देखना कुछ और नहीं बल्कि इसान के लिए अपने देशकालों से दूर होना है। इसलिए जब कोई विकास करने के लिए भूजल के मार्केट में एक तो हायों पास वर्षानन तकनीकों से मेल खाने वाले कानूनों का अधार था दूसरे व्यवस्थित अनुश्रवण

श्री बागेश्वर धाम



अरविन्द पाण्डे

श्रीबागेश्वर धाम का समर्थन : श्री बागेश्वर धाम एक सिद्ध तीर्थ है जहां श्री हनुमान जी महाराज की सजीव प्रतिमा विराजित है।

पटना के समीप तेरत पाली मठ के नवुंगत कथा में 50 लाख लोगों ने शिरकत की। आखिर कौतूहल स्वाभाविक है संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में।

श्रीहनुमान जी महाराज के कृपाप्रसाद सत्र श्री धीरेन्द्रकृष्ण शास्त्री जी वही के साधक हैं और सनातन धर्म की निरंतर विश्वव्यापी कार्यक्रम कर रहे हैं।

संत श्री शास्त्री अपनी सभाओं में जिन अधिनियम कार्यों का आश्रम मुलक प्रदर्शन करते हैं उन कार्यों के करने वालों को आजकल सरे विश्व में विज्ञान की भाषा में मैटेलिस्ट और माइड रीडर आदि कहा जाता है।

इस अधिनियम की अनुसूची में काला जादू, अधोरी क्रिया आदि का विस्तृत सूचीकरण है और केवल उन्हीं अनुचित क्रियाओं के लिए ही अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत नियुक्त सतरका अधिकारी मुकदमा दर्ज करा सकता है।

किंतु, सोशल मीडिया पर मिथ्या प्रवाद प्रचारित किया गया कि संत श्री धीरेन्द्रकृष्ण शास्त्री के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा सकता है।



सैन्य जानकारी
साझा करने के
मानले में दो गिप्तार
नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आइटी हार्डवेयर के लिए उत्तादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को मंजूरी दे दी है। इस पर 17 हजार करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यव होगा। कार्यक्रम की अवधि 6 वर्ष है। इससे 2,430 करोड़ रुपये के निवेश प्राप्त की ओफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है।

डीयू ने पेटेंट पर 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू

नयी दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने एक नयी पहल करते हुए समय की मांग के अनुरूप पेटेंट पर एक सर्टिफिकेट कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स औन पेटेंट की शुरूआत की है। कोर्स का शुभारंभ विश्वविद्यालय के वाइस रीगल लॉज के अकादमिक परिषद हॉल में बुधवार को किया गया।

27वीं बार एवरेस्ट फतह कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

काठामांडू। नेपाल के कामिरिता शेरपा ने 27वीं बार बुधवार की सुबह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शेरपा 54 साल के हो गये हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने विवाह की बैठक टाली

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में अगले सप्ताह प्रसारित विवाह देशों की बैठक टाल दी गयी है। आस्ट्रेलिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की बैठक में न आने के फैसले की वजह से यह फैसला किया है। चार प्रमुख देशों भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संगठन विवाह की बैठक अगले सप्ताह विवाहित की गयी।

पीएलआई योजना 2.0 को मिली मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट का फैसला : 2430 करोड़ रुपये निवेश प्राप्ति की संभावना

एजेंसी

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आइटी हार्डवेयर के लिए उत्तादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को मंजूरी दे दी है। इस पर 17 हजार करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यव होगा। कार्यक्रम की अवधि 6 वर्ष है। इससे 2,430 करोड़ रुपये के निवेश प्राप्त की ओफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है।



जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अशवनी वैष्णव ने कहा कि पीएलआई योजना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोबाइल और टेक्नोलॉजी उपकरणों के उत्तादन के क्षेत्र में सफल रही है। इससे इन क्षेत्रों में उत्तादन बढ़ रहा है और भारत इनका बढ़ावा निर्धारित कर बना है। उन्होंने कहा

कि अब सरकार आइटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए भी योजना लेकर आयी है। इससे इन क्षेत्र का उत्तादन 3.35 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ेगा। क्षेत्र को 2,430 करोड़ रुपये के निवेश प्राप्त होगा और प्रत्यक्ष तौर पर 75 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। वहाँ, अग्रवाल

खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन में युरिया के लिए 70 हजार करोड़ रुपये और डायमोनियम फॉर्सेट (डीएपी) के लिए 38 हजार करोड़ रुपये सहित कुल 1.08 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनवीएस) दरों में संशोधन के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मादविया ने बताया कि दूनिया भर में उर्वरकों के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है।

विवान को ओलंपियाड ऑफ इंगिलिश लैंग्वेज में चतुर्थ स्थान



परिचय दिया है। विवालय की डायरेक्टर (एकेडमिक) रंजना स्वरूप एवं प्रिंसिपल जसमीत कौर ने विवान को सर्टिफिकेट एवं मेडल देकर उसकी उपलब्धि पर हर्ष जताएं हुए। कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, वर्ष 2024 में 6.7 फीसदी की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र ने जारी एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊंची व्याज दरों दराव के तथा कमज़ोर बाहरी मांग की वजह से देश के निवेश और नियर्ति पर दबाव बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की 2023 के मध्य तक वैश्वक अर्थिक स्थिति और संघवानाएं शीर्षक वाली ये रिपोर्ट मंगलवार को बहाने रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कैलेंडर वर्ष 2023 में 5.8 फीसदी और 2024 में 6.7 फीसदी की संधारित और नियर्ति के बराबर रहेगी। विवान की इस उपलब्धि पर समस्त शारदा म्लोबल परिवार ने उसके उज्ज्वल भवियत की कामना की है।

परिचय दिया है। विवालय की डायरेक्टर (एकेडमिक) रंजना स्वरूप एवं प्रिंसिपल जसमीत कौर ने विवान को सर्टिफिकेट एवं मेडल देकर उसकी उपलब्धि पर हर्ष जताएं हुए। कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, वर्ष 2024 में 6.7 फीसदी की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र ने जारी एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊंची व्याज दरों दराव के तथा कमज़ोर बाहरी मांग की वजह से देश के निवेश और नियर्ति पर दबाव बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की 2023 के मध्य तक वैश्वक अर्थिक स्थिति और संघवानाएं शीर्षक वाली ये रिपोर्ट मंगलवार को बहाने रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की समर्थकों के मध्य तक वैश्वक अर्थिक स्थिति और संघवानाएं शीर्षक वाली ये रिपोर्ट मंगलवार को बहाने रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कैलेंडर वर्ष 2023 में 5.8 फीसदी और 2024 में 6.7 फीसदी की संधारित और नियर्ति के बराबर रहेगी। विवान की इस उपलब्धि पर समस्त शारदा म्लोबल परिवार ने उसके उज्ज्वल भवियत की कामना की है।

जब तक शरीर में प्राण रहेगा, बिहार आते रहेंगे : बाबा बागेश्वर

एजेंसी

पटना। बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 13 मई को पटना आये थे। नौबतपुर के तरेत पाली मठ में उनके पांच दिवसीय हनुमंत कथा को सुनने लिए देश के कठोरों को नें से लोग पहुंचे बुधवार (17 मई) की उनके कार्यक्रम का समाप्त हो गया। इसके बाद वे पटना एवरेस्ट से मध्य प्रदेश चले गये। बिहार से वापस जाने के दौरान बागेश्वर बाबा ने कहा, जबतक शरीर में प्राण रहेगा बिहार आते रहेंगे।

बिहार वासियों पर बागेश्वर बाबा की दौरान बागेश्वर बाबा ने बारे पर जमकर सियासत भी की। उन्होंने विवाह से पहुंचे का बाबा की वजह से देश के निवेश और नियर्ति पर दबाव बना रहेगा।

बोलती रही है। 13 मई से पहले से ही भूमों के पटना पहुंचे का सिलसिला शुरू हो गया था। वैसे, बागेश्वर बाबा को बिहार दौरे पर जमकर सियासत भी हुई। राजद ने जाने की वजह से देश के निवेश और नियर्ति पर दबाव बना रहेगा।

पटना में पांच दिवसीय कार्यक्रम का हुआ समाप्त



वहाँ भाजपा ने भी मोर्चा संभालते हुए हर कदम पर बागेश्वर सरकार का समर्पण किया। बिहार में बागेश्वर बाबा को बिहार के बागेश्वर बाबा की नीति वाली पर दबाव भी की। उन्होंने विवाह से पहुंचे का बाबा की वजह से देश के निवेश और नियर्ति पर दबाव बना रहेगा।

बोलती रही है। 13 मई से पहले से ही भूमों के पटना पहुंचे का सिलसिला शुरू हो गया था। वैसे, बागेश्वर बाबा को बिहार दौरे पर जमकर सियासत भी हुई। राजद ने जाने की वजह से देश के निवेश और नियर्ति पर दबाव बना रहेगा।

बोलती रही है। 13 मई से पहले से ही भूमों के पटना पहुंचे का सिलसिला शुरू हो गया था। वैसे, बागेश्वर बाबा को बिहार दौरे पर जमकर सियासत भी हुई। राजद ने जाने की वजह से देश के निवेश और नियर्ति पर दबाव बना रहेगा।

बोलती रही है। 13 मई से पहले से ही भूमों के पटना पहुंचे का सिलसिला शुरू हो गया था। वैसे, बागेश्वर बाबा को बिहार दौरे पर जमकर सियासत भी हुई। राजद ने जाने की वजह से देश के निवेश और नियर्ति पर दबाव बना रहेगा।

बोलती रही है। 13 मई से पहले से ही भूमों के पटना पहुंचे का सिलसिला शुरू हो गया था। वैसे, बागेश्वर बाबा को बिहार दौरे पर जमकर सियासत भी हुई। राजद ने जाने की वजह से देश के निवेश और नियर्ति पर दबाव बना रहेगा।

बोलती रही है। 13 मई से पहले से ही भूमों के पटना पहुंचे का सिलसिला शुरू हो गया था। वैसे, बागेश्वर बाबा को बिहार दौरे पर जमकर सियासत भी हुई। राजद ने जाने की वजह से देश के निवेश और नियर्ति पर दबाव बना रहेगा।

बोलती रही है। 13 मई से पहले से ही भूमों के पटना पहुंचे का सिलसिला शुरू हो गया था। वैसे, बागेश्वर बाबा को बिहार दौरे पर जमकर सियासत भी हुई। राजद ने जाने की वजह से देश के निवेश और नियर्ति पर दबाव बना रहेगा।

बोलती रही है। 13 म